

सिटी आस-पास संदेश

खबर संक्षेप

उरुवा ब्लाक परिसर में ग्राम प्रधानों का एक दिवसीय प्रदर्शन आज

मेज रोड। उरुवा ब्लाक परिसर में ग्राम प्रधानों का एक दिवसीय प्रदर्शन आज ब्लॉक परिसर में प्रधान संघ अध्यक्ष राजेश द्विवेदी के नेतृत्व में आयोजित किया जाएगा। उत्तर राजेश की जानकारी देने हुए अध्यक्ष राजेश द्विवेदी ने बताया कि प्रधानों के हक के लिए जारी संसर्ख की कड़ी में सोमवार को प्रधान अध्यक्ष की अगुआई में शाति पूर्वक राजना प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम जापन की राजनीति पर धारणा की जाएगी। उन्होंने कहा कि जब तक पंचायती राज में निहित प्रधानों के हक नहीं मिल जाते तब तक आदेलन जारी रहेंगे।

अरेल घाट पर चला सफाई अभियान

नैनी। अरेल घाट पर रविवार को सरस्वती सामाजिक सेवा संस्थान की ओर से सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान मौजूद लोगों ने पक्के घाट से लोकर गंगा युग्मा तट पर सफाई कार्य की विधा किया। इस मोक्षे पर वर्धु वृद्ध की लाश और विवाही लोगों की दूध की लाश दूँहे में लगी हुई है। गोताखोरों की कड़ी मशक्त के बावजूद वृद्ध की लाश नियमित मौजूद होती है। डब्बने की खबर जैसे ही उत्तर पर्जिनों के बीच पहुंची उनके होश उड़ गए और दहाड़े मारकर विलास करते हुए गंगा घाट पर पहुंच गए और वृद्ध की लाश पानी से बार कर लिया जाने की इंतजार कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक चरवा थाना श्रेष्ठ के चौराठीहांगांव निवासी मनू मिश्रा उम्र 20 वर्ष पुत्र दया शंकर श्रेष्ठ रविवार सुबह आठ बजे घर से गंगा स्नान करते हुए पहले घाट पर चला आए, थे, स्नान करते समय समर्त कई लोग मौजूद रहे।

सम्पादकीय

भ्रष्टाचार के गढ़

नोएडा के सुपरटेक मामले में भ्रात्याचार की जांच के लिए बनाए गए विशेष जांच दल (एसआईटी) ने काम शुरू कर दिया है। यह जांच दल अब नोएडा विकास प्राधिकरण के उन अधिकारियों से पूछताछ करेगा जो सुपरटेक मामले से जुड़े रहे थे। साथ ही सालों पुरानी संबंधित फाइलें भी खंगाली जाएंगी, ताकि पता चल सके कि किस-किस स्तर पर प्राधिकरण के अधिकारी भवन निर्माता पर मेहरबान रहे और उन्हें बेजा फायदा पहुंचाते रहे। इस कवायद का कोई फायदा तभी होगा जब जांच दल तत्परता और निष्पक्षता के साथ मामले की तह तक जाएगा और तथ्यों का पता लगा कर दोषियों को कठघरे में लाने के प्रयास करेगा। और तभी भविष्य में भवन निर्माताओं की मनमानी पर लगागम लग सकेगी। गैरतरलब है कि पिछले हफ्ते सर्वोच्च अदालत ने नोएडा में बनी सुपरटेक की चालीस-चालीस मजिला दो इमारतों को गिराने का निर्देश दिया था। ये दोनों इमारतें जिस तरह से खड़ी कर दी गई थीं, वह अपनी तरह है कि काम गंभीर मामला नहीं है। सुपरटेक का मामला बता रहा है कि जमीनों के आंवटन से लेकर भवन निर्माण तक में प्राधिकरण के अधिकारियों और भवन निर्माताओं की सांठगांठ कितनी जबर्दस्त है। इससे यह भी पता चलता है कि अरबों रुपए के भवन निर्माण कारोबार में भवन निर्माता किस तरह से प्राधिकरण के अधिकारियों को पैसे के बल पर अपने कब्जे में करके उनसे अपने मनमुताबिक फैसले करवाते चले जाते हैं। इससे प्राधिकरण को भारी राजस्व हानि तो होती ही है।

निसदेह यह अदालत के फैसले से बन दबाव का ही नतीजा है कि जांच को लेकर प्रदेश सरकार को सक्रिय होना पड़ा। सर्वोच्च अदालत ने सुपरटेक की दोनों इमारतों को गिराने के साथ ही प्राधिकरण के उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश भी दिए हैं। जिनके कार्यकाल में सब होता चला गया। इसलिए अब प्रदेश सरकार 2004 से 2017 के बीच नोएडा प्राधिकरण में तैनात उन अधिकारियों की सूची बनवा रही है जो सुपरटेक मामले से जुड़े रहे थे। सुपरटेक का मामला सिर्फ प्राधिकरण की ही नहीं, बल्कि राज्य सरकार की कार्य संस्कृति पर भी सवाल खड़े करता है। इससे तो लगता है कि सरकार में ऊपर से नीचे तक कोई यह देखने वाला नहीं है कि कहां क्या गलत हो रहा है। सवाल यह है कि क्या प्राधिकरणों में कहाँ कोई निगरानी का तंत्र नहीं हैं और अगर हैं तो फिर वर्षों तक इसके महकमे का निगरानी तंत्र करता क्या रहा शीर्ष अधिकारियों को क्या जरा भी भनक नहीं लग पाई कि उनके मातहत किस तरह से नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए भवन निमाताओं के हितों को पूरा कर रहे हैं। ऐसी इमारतें कोई एक दिन में तो खड़ी हो नहीं जातीं। जाहिर है, प्राधिकरण के अधिकारी मेहरबान बने रहे और भवन निमाता अपना काम करते गए। मामला सिर्फ सुरपरटेक तक ही सीमित नहीं है। नोएडा में कई नामी बिल्डरों ने घर खरीदने वालों के साथ जिस तरह का धोखा किया है, वह भवन निमाताओं और प्राधिकरण के अधिकारियों की सांठगांठ का ही नतीजा है। आज भी नोएडा में डेढ़ लाख और ग्रेटर नोएडा में दो लाख लोगों को फ्लैटों का कब्जा नहीं मिला है। पिछले डेढ़ दशक के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भवन निर्माण कारोबार तेजी से पनपा है। भवन निमाताओं को जमीनों के आवंटन में भारी भ्रष्टाचार की खबरें सामान्य बात हो चली हैं। ज्यादात हैरानी की बात तो यह है कि पिछले डेढ़ दशक में कई सरकारें आईं, लेकिन प्राधिकरणों में फैले भ्रष्टाचार पर लगाने का साहसरण किसी ने नहीं दिखाया। इसी का नतीजा है कि आज प्राधिकरण भ्रष्टाचार के गढ़ में तब्दील हो गए हैं।

थोड़ा माओ से सबक लें मोदी

चीनी इतिहासकार वृंत्युआग बताते हैं कि द ग्रेट लॉप के दुष्परिणामों की वजह से 5 करोड़ 60 लाख लोग मरे गये। हालांकि चीनी लीडरशिप इस सवाल पर चुप्पी साथे हुए है कि 1962 में जब देश अकाल और भयानक आर्थिक संकट से गुजर रहा था, तब भारत-चीन युद्ध छेड़ने की जरूरत क्या थी शांघाई से शाओशान के लिए 11सौ किलोमीटर का सफर। केवल यह महसूस करने के बासे कि माओ का बचपन किस माहौल में गुजरा था। बस ठान लिया था कि सबसे पहले माओ की जन्मस्थली जाना है, फिर पैद्यिंग का थ्येनआनमन स्कवायर, जहां वो दफन हैं। सैंट्रल चाइना स्थित शाओशान। वहां पहुंचा तो, फूस और खपरैल का दो मंजिला दिव्य मकान, यहाँ 26 दिसंबर 1893 को जन्मे थे माओस्तेर तुंग। सामने खेत, नहर और पार्श्व में पहाड़। हुनान प्रांत की छोटी सी काउंटी शाओशान। बमुशिकल एक लाख लोगों की आबादी होगी, मगर माओ की जन्मस्थली के कारण उनके शैदाइयों के लिए तीर्थस्थल जैसा है।

विदेशी के नाम पर मेरे जैसा भारतवासी (इंतु-रन) और इक्के-दुक्के उत्तर कोरियाई दिख रहे थे। वहां पहुँचे पर्यटकों में देशवासियों की सख्ता सर्वाधिक। माओ त्सेतुंग के पिता, माओ यीछंग जर्मीदार थे। चार भाइयों में सबसे छोटे माओ त्सेतुंग, जिन्होंने पास के प्राइमरी स्कूल में चूंचिंग (कन्प्युशियन क्लासिक्स) की पढ़ाई की थी। वहां पता चला, बालक माओ त्सेतुंग के आदर्श कोई चीनी आइकॉन नहीं, बल्कि जाज वाशिंगटन और नेपोलियन थे। बाद में माओ ने प्रांतीय राजधानी छांगसा में सेकंडरी स्कूल की कक्षा में दाखिला लिया और सुन यात-सेन के राष्ट्रवादी विचारों से प्रभावित होते रहे। सुन यात-सेन चीनी गणतंत्र के संस्थापक और राष्ट्रपिता थे। जब चीन चेयरमैन माओ के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1949 को जनवादी गणतंत्र बना, माओ ने राष्ट्रपिता का ओहदा हटाकर सुन यात-सेन को लोकतांत्रिक क्रांति का अग्रदृष्ट धोषित कर दिया। एक नेता जब महान होने की ओर अग्रसर होता है, अपने पूर्ववर्ती की लकीर छोटी करता है, इसे आप एशियाई राजनीति की रवायत समझ लीजिए, जिसकी शुरूआत आधुनिक चीन से होती दिखती है। राष्ट्रपिता शी चिनफिंग आज की तारीख में चेयरमैन माओ से भी महाकाय नेता के रूप में निरूपित हो चुके हैं। गुरुवार को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना (सीपीसी) की केंद्रीय समिति का छठा समग्र सत्र (प्लॉनरी सेशन) संपन्न हुआ। इसमें पूरे सौ साल का लेखा-जोखा प्रस्तुत करते हुए जौ प्रस्ताव पारित हुआ, उससे यही निष्कर्ष निकलता है कि शी जैसा कोई नहीं। चीन को विश्व पटल पर लाने में, उसकी आर्थिक-सामाजिक विसंगतियों को दूर करने में किसी ने

योजनाबद्ध तरीके से काम किया, तो वो सिर्फ् शी चिनफिंग है। पेइचिंग में 8 से 11 नवंबर के बीच 19वीं सीपीसी सेंट्रल कमेटी की बैठक हुई। शी इस सर्वोच्च कमेटी के महासचिव हैं। शी सर्वोच्च नेता बने रहेंगे, और बिना किसी वैधानिक बाधा के शासन करेंगे, यह छठे प्लॉनरी सेशन में तय हो चुका। चार दिवसीय सत्र में माओ त्सेतुंग और उनके बाद के चार शासकों के कालखंड का लेखा-जोखा प्रस्तुत हुआ। तंग श्याओफिंग, चियांग जेमिन, हू चिन्थाओ और शी चिनफिंग, इन चार शासकों में सबसे महान कौन था, माओ का कितना बड़ा योगदान था, उसपर जो भी प्रस्ताव रखे गये, उपस्थित सदस्यों ने हाथ उठाकर समर्थन किया।

19वीं सीपीसी सेंट्रल कमेटी के छठे प्लॉनरी सेशन में जो प्रस्ताव रखे गये, उसका सारांश यह है कि चेयरमैन माओ के समय नव लोकतांत्रिक क्रांति का आविर्भाव हुआ। माओ के रहते समाजवादी क्रांति और उसका

आरोप-प्रत्यारोप की बजाय पड़ोसी राज्य मिलकर प्रयास करें तो यमुना साफ हो जायेगी

ललित गर्ग

सार्थक एवं प्रभावी उपचार होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लंबे समय से यह समस्या बनी रहने के बावजूद इसके समाधान का रास्ता निकाल को कोई तैयार नहीं है। बल्कि यमुना के नाम पर राजनीतिक दल जमकर राजनीति करते हैं, एक दूसरे दलों एवं पड़ोसी राज्य एक-दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर अपनी जिम्मेदारी से पला झाड़ लेते हैं। यमुना के प्रदूषण के लिए दिल्ली सरकार पड़ोसी राज्यों- हरियाणा और उत्तर प्रदेश के इसका जिम्मेदार ठहरा रही है, तो दूसरी ओर ये राज्य इसके लिये दिल्ली सरकार की गलत नीतियों एवं उदासीनता को देखी मानते हैं। कुल मिलाकर यमुना का यह संकट राजनीति के दुश्क्रम में उलझ कर रह गया है। ऐसे बड़ा सबाल यह है कि यमुना प्रदूषण सुकृत कैसे हो लगातार बढ़ता दिल्ली का जल सकट इन स्थितियों में कैसे समाधान पाये जब आपके द्वारा कसीढ़ियां मैली हैं तो अपने पड़ोसी की छत पर गन्दी का उलाहना मार दीजिए। हमें कुछ ऐसा करना होगा ताकि मरने के बाद स्वर्ग में रहने के बजाय मरने से पहले स्वर्ग रहे। विडम्बनापूर्ण त्रासदी है कि दिल्ली हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों की औद्योगिक इकाइयों से ज अपशिष्ट और जहरीले रसायन निकलते हैं, उन्हें यमुना में छोड़ दिया जाता है। वैसे यह समस्या देश की तमाम छोटी-बड़ी नदियों के साथ है नदियों के प्रति हमारा यह उपेक्षापूर्ण रवैया हमारी जीवनरक्षक नदियों के जहरीला बनाता रहा है। ये नदियां जिन शहरी इलाकों खासतौर से औद्योगिक शहरों से गुजरती हैं, वहां का अपशिष्ट इनमें बहा दिया जाता है। इसलिए आज ज्यादातर नदियां खतरनाक स्तर तक प्रदूषित हो चुकी हैं। दिल्ली की समस्या इसलिए ज्यादा गंभीर एवं घातक होती जा रही है कि एक यमुना ही तो है जो दिल्ली के लिये शुद्ध जल आपूर्ति का साधन है दिल्ली में साफ पानी के स्रोत काफी कम हैं, ऐसे में यमुना नदी पर निर्भरत जरूरत से ज्यादा रहती है। राजधानी दिल्ली में साफ पानी की बड़ी समस्या है। सिर्फ जगह बदलती है, लेकिन गंदे पानी की शिकायत से जगह समान रूप से देखने-सुनने को मिल जाती है। इसकी एक बड़ी वजह यमुना नदी का वो गंदा पानी भी है जो समय के साथ ना सिर्फ और ज्यादा विषेला होता जा रहा है, बल्कि कई बीमारियों का कारण भी बरहा है। यमुना में प्रदूषण का स्तर खतरनाक है और दिल्ली से आगे ज कर ये नदी मर जाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि इसकी वजह औद्योगिक प्रदूषण, बिना उपचार के कारखानों से निकले दूषित पानी की सीधी नदी में गिरा दिया जाना, यमुना किनारे बसी आबादी मल-मूत्र और

गंदी को सो सधे नदी में बहा देती है। साथ ही धार्मिक वजहों के चलते तमाम मूर्तियों व अन्य अवशिष्ट पूजा सामग्री का नदी में विसर्जन करने की परम्परा। औद्योगिक प्रदूषण, मल-मत्र और धार्मिक सामग्री का नदी में विसर्जन प्रदूषण की मुख्य वजह है, लेकिन इनमें सबसे खतरनाक है रासायनिक कचरा। ठंड के मौसम में यह समस्या विकराल रूप धारण कर लेती है। ऐसे में यमुना को प्रदूषित होने से कैसे बचाया जा सकता है यमुना की प्रदूषण-मुक्ति के लिये सरकार के साथ-साथ जन-जन को जागाना होगा। सरकार की सख्ती एवं जागरूकता ज्यादा जरूरी है। यमुना प्रदूषण से निपटने के लिए राष्ट्रीय हरित पंचाच, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जैसे निकाय औद्योगिक इकाइयों के लिए समय-समय पर सख्त नियम बनाते रहे हैं। पर लगता है कि इनके दिशानिर्देशों पर अमल करवाने वाला तंत्र कमज़ोर साधित हो रहा है। वरना क्या कारण है कि सख्ती के बाद भी औद्योगिक कचरा और जहरीले रसायन यमुना में बहाए जा रहे हैं औद्योगिक इकाइयों को सख्त हिदायत है कि वे तरल कचरा नदियों में प्रवाहित न करें। पर जिस सरकार, उसके महकमे और कानून प्रवर्तन एंजेसी पर इसे सुनिश्चित करवाने की जिम्मेदारी है, लगता है वह काम ही नहीं कर रही। यह एक तरह का भ्रष्टाचार है, गैर-जिम्मेदारी है। यमुना के प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को मिलकर काम करने की जरूरत है, न कि राजनीति करने की। जब तक तीनों राज्य साथ बैठ कर चर्चा नहीं करेंगे, कार्योजनाओं पर कदम नहीं बढ़ाएंगे और एक दूसरे पर आरोप मढ़ते रहेंगे तो कोई नतीजा नहीं निकलने वाला, बल्कि दिनोंदिन यह संकट गहराता जाएगा। कुछ समस्याएं राजनीतिक नफानुकसान से ऊपर होती हैं। उन्हें राजनीतिक नजरिये से नहीं, मानवीय नजरिये से देखना होता है। अन्यथा जीवन मुश्किल ही नहीं, असंभव हो जायेगा। मनुष्य के भविष्य के लिए यह चिन्ता का बड़ा कारण है। दिल्ली की यमुना इसी प्रकार अगर प्रभावित एवं प्रदूषित होती रही तो अगली शताब्दी में दिल्ली की बहुत कुछ विशेषताएं समाप्त हो जाएंगी। क्या आप ऐसी सुधर हाचाहेंगे जब दिल्ली का जीवन घोर अंधेरों से घिरा हो विडम्बना यह है कि इस ओर हमारे दायित्व के प्रति हम सबने आंखें मुंद रखी हैं। हिंदुस्तान का जिस तरह का मौसम चक्र है उसमें हर नदी चाहूँ वो कितनी भी प्रदूषित क्यों न हो, साल में एक बार वर्षा के बक्स खुद को फिर से साफ करके देती है, पर इसके बाद हम फिर से इसे गंदा क्यों कर देते हैं अगर दिल्ली की यमुना को अप्रदूषित करना है तो एक-एक व्यक्ति को उसके लिए सज्ज होना होगा। प्रकृति ने जो हमें जीवनदायिनी नदियां दी हैं जो रोज नया जीवन देती हैं, उसे हम प्रदूषित नहीं करें।

सागरनील सिन्हा

तासरा बार मुख्यमंत्री के रूप में पाटी सुप्रिया ममता बनजा का वापसी। बाद, टीएमसी को पता है कि बंगल के बाहर पार्टी को एक बार फिर फैलाने का यह सबसे अच्छा समय है। हालांकि टीएमसी एक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन इसकी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खतरे में है और 2024 में चुनाव आयोग द्वारा इसकी समीक्षा किए जाने पर यह स्थिरता खोने की उम्मीद है। ममता की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं के लिए राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बनाए रखना महत्वपूर्ण है। अपनी पहली रैली में, अभिषेक ने घोषणा की कि 2023 के राज्य विधानसभा चुनावों में, टीएमसी सत्तारूप भाजपा और मुख्य विपक्षी माकपा को हराकर राज्य में सरकार बनाएगी। जैसा कि अपेक्षित था, अभिषेक की रैली ने मीडिया का ध्यान आकर्षित किया। हालांकि रैली इतनी सफल नहीं थी, पार्टी को त्रिपुरा उच्च न्यायालय को धन्यवाद देना चाहिए, जिसने आदेश दिया था कि रैली केवल 50

लोगों तक सीमित हो। इसी आदेश ने टीएमसी का चेहरा बचा लिया। पार्टी की रणनीति मैडिया की सुर्खियां बटोरने की ज्यादा लगती है और अब तक वह ऐसा करने में सफल रही है। अगरतला में अधिकारीकी मौजूदगी में पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्य मंत्री राजीव बनर्जी का पार्टी में वापस आना इस बात का संकेत है। बंगाल विधानसभा चुनावों से पहले, राजीव टीएमसी छोड़ कर भाजपा में शामिल हो गए और अपनी डोमेजूर सीट से चुनाव लड़ा, जहां वह बड़े अंतर से हार गए। हालांकि उन्हें हाल ही में भगवा पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारी समिति का सदस्य बनाया गया था लेकिन उन्होंने राज्य चुनावों में भाजपा की ओर के बाद टीएमसी में

त्रिपुरा में तृणमूल कांग्रेस की कमज़ोर कड़ी है संगठन

कांग्रेस के पास अभी भी वाट बस ह, जो 2018 के राज्य विधानसभा चुनाव में भाजपा की ओर स्थानांतरित हो गया था, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनावों में पार्टी में एक वर्ग वापस आ गया। हालांकि टीएमसी कई जगहों पर कांग्रेस के मतदाताओं को आकर्षित करने में सफल रही है, लेकिन तथ्य यह है कि अनुकूल मीडिया घरानों के एक वर्ग से शीर्षक वरेज प्राप्त करने के बावजूद पार्टी अपने मौजूदा परिवश्य में आगामी 2023 के राज्य विधानसभा चुनावों के लिए अभी भी एक कमज़ोर खिलाड़ी है। अभी तक, राज्य में लड़ाई भाजपा और माकपा के नेतृत्व वाले वामपोर्चं के बीच है। तृणमूल कांग्रेस त्रिपुरा में पैर जमाने के लिए फिर से प्रयास कर रही है, जहां पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने 31 अक्टूबर को अपनी पहली रैली की। इसने पूर्वोत्तर राज्य में पार्टी का विस्तार करने के लिए अतीत में कई प्रयास किए थे। पश्चिम बंगाल में

तासरा बार मुख्यमंत्री के रूप में पाटी सुप्रिया ममता बनजा का वापसी। बाद, टीएमसी को पता है कि बंगल के बाहर पार्टी को एक बार फिर फैलाने का यह सबसे अच्छा समय है। हालांकि टीएमसी एक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन इसकी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खतरे में है और 2024 में चुनाव आयोग द्वारा इसकी समीक्षा किए जाने पर यह स्थिरता खोने की उम्मीद है। ममता की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं के लिए राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बनाए रखना महत्वपूर्ण है। अपनी पहली रैली में, अभिषेक ने घोषणा की कि 2023 के राज्य विधानसभा चुनावों में, टीएमसी सत्तारूप भाजपा और मुख्य विपक्षी माकपा को हराकर राज्य में सरकार बनाएगी। जैसा कि अपेक्षित था, अभिषेक की रैली ने मीडिया का ध्यान आकर्षित किया। हालांकि रैली इतनी सफल नहीं थी, पार्टी को त्रिपुरा उच्च न्यायालय को धन्यवाद देना चाहिए, जिसने आदेश दिया था कि रैली केवल 50

देश/विदेश संदेश

सेना से जुड़ी खुफिया
जानकारी लीक करने वाला

जवान पट्टना में गिरफतार

पट्टना। सेना के जवान को

खुफिया सूचना लीक करने के

आरोप में गिरफतार किया गया है।

पुणे में तेजत जवान गणेश प्रसाद

को केंद्रीय खुफिया एजेंस से मिले

इनहुए के आधार पर बिहार एटीएस

ने खगोल पुलिस और मिलिट्री

ईटीएलजेस के सहयोग से गिरफतार

करने के बाद जनकारी मुहूर्या

करना की बात उसने स्वीकार की

कर ली है। फिलहाल उससे खगोल

थाना में पूछताछ हो रही है। सूत्रों

में जानकारी सेथा का जाना गणेश

प्रसाद (अस्थावां, नालंदा)

पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी

आईएसआई की महिला एजेंस के

संपर्क में था। जानशुर में तेजती के

द्वारा जनकारी ने उस ही ट्रैप में

फ़लाया। बताया जाता है कि उक्त

महिला ने खुफिया को नौसेना का

मेडिकल स्टॉफ बताकर गणेश से

देखनी की।

रक्षा मंत्रालय की नई सूची से अगस्ता वेस्टलैंड गायब, 6 कंपनियां ब्लैक लिस्ट और 13 स्पेंड



टेनोलॉजीज काइनेटिक्स लिमिटेड (एसटीए), इंडियाइल मिलिट्री इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आईएसआई), टीएस किसान एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, आरके मशीन ट्रूस्स लिमिटेड, आरके मशीन ट्रूस्स लिमिटेड (लुधियाना), राजनेश्वर एंड डिफेंस (आरएडी), ज्यूरिख

और कॉर्पोरेशन रक्षा (रूस) शामिल हैं। हालांकि, सूची में आगता वेस्टलैंड और इसकी मूल फर्म लियोनार्डों का नाम नहीं है, जिसे एक फर्मों के साथ कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया गया है। रोचक बात ये है कि इस सूची में 6 फर्मों को ब्लैकलिस्ट किया गया है। इन नई सूची में 6 कंपनियों के साथ कारोबार रोक दिया गया है। रोचक बात ये है कि इस सूची में अगस्ता वेस्टलैंड का नाम नहीं है। रखिवार को रक्षा मंत्रालय ने अनुबंध कंपनियों नई सूची जारी की। जिसमें छह कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया गया है। जबकि 13 कंपनियों के साथ कारोबार रोक दिया गया है। रोचक बात ये है कि इस सूची में सूची के साथ कंपनियों को कारोबार के लिए संस्केड कर दिया है। रखिवार को रक्षा मंत्रालय ने खुफिया एजेंसी आईएसआई की महिला एजेंस के संपर्क में था। जानशुर में तेजती के द्वारा जनकारी ने उस ही ट्रैप में फ़लाया। बताया जाता है कि उक्त महिला ने खुफिया को नौसेना का मेडिकल स्टॉफ बताकर गणेश से देखनी की।

पूर्वोत्तर में अशांति फैलाने की साजिश रच रहा है चीन? मणिपुर हमले के बाद फिर उठे सवाल

नई दिल्ली। मणिपुर में म्यांगार

बॉर्डर के पास आतंकी हमले में

शनिवार को 5 सैनिक शहीद हो

गए। इसमें सेना के कर्नल के अलावा

उनकी पत्नी और 8 साल का बेटा

भी शामिल हैं। इस घायल हमले के बाद पूर्वोत्तर में बिद्रोही गुटों को

चीन की ओर से संभावित समर्थन

ने फ़िर ध्यान खींचा है। चीन पर

नजर रखने वालों और सुरक्षा

अधिकारियों ने रखिवार को कहा

कि सीमा पर तात्पर के बीच पड़ासी

क्षेत्र में असामी फैलाने की साजिश

रच सकता है। यह पहली बार नहीं है जब बिद्रोही सूर्हों के साथ चीनी संबंध जांच के दावे में आए हैं।

बिद्रोही की मिलिटरी बातों को खराकर सवाल पहले भी उठे हैं। अक्टूबर

2020 में चीन की प्रोप्रोगेंडा मार्गीनी

ने ताइवान से व्यापार समझौते को

लेकर भारत को धमकी दी थी

कि बिंगिंग वॉर्ट में अलावाकरियों

को मास्थन और सिविल कामों भारत

के अंत में समर्थन देना बढ़ा

करके जवाब दे सकता है।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि, हवा देने की संभावना वरकर है। यह पहली बार नहीं है जब बिद्रोही सूर्हों के साथ चीनी संबंध जांच के दावे में आए हैं।

बिद्रोही की अप्रोगेंडा मार्गीनी

ने अप्रैल और जून में अलावाकरियों

को धमकी दी है। अप्रैल

2020 में चीन की प्रोप्रोगेंडा मार्गीनी

ने ताइवान से व्यापार समझौते को

लेकर भारत को धमकी दी है।

अप्रैल और जून में अलावाकरियों

को मास्थन और सिविल कामों भारत

के अंत में समर्थन देना बढ़ा

करके जवाब दे सकता है।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि, हवा

देने की संभावना वरकर है। यह पहली

बार नहीं है जब बिद्रोही सूर्हों के

साथ चीनी संबंध जांच के दावे में

आए हैं।

इन्हीं ने बिद्रोही की अप्रोगेंडा

मार्गीनी को खराकर सवाल

पूछ रखा है कि वे क्या करना चाहते हैं।

बिद्रोही की अप्रोगेंडा मार्गीनी

ने अप्रैल और जून में अलावाकरियों

को मास्थन और सिविल कामों भारत

के अंत में समर्थन देना बढ़ा

करके जवाब दे सकता है।

लंदन के लीवरपूल अस्पताल के

बाहर कार में धमाका, एक की मौत

नई दिल्ली, एजेंसी। लंदन के

लीवरपूल इंस्टीट्यूट के बाहर

एक कार में धमाका हो गया।

इस घटना में एक अन्य कार

में धमाका हो गया।

प्रकाशित एवं अनुसंधान संस्थान

झूमी, प्रयागराज 211019 से

प्रकाशित एवं रामा प्रिंटिंग प्रेस

53/25/1ए बेटी रोड नया कट्टरा

प्रयागराज से मुद्रित।

मुद्रक/प्रकाशक

स्वामी श्री योगी सत्यम क्रियायोग

आश्रम एवं अनुसंधान संस्थान

झूमी, प्रयागराज 211019 से

प्रकाशित एवं रामा प्रिंटिंग प्रेस

53/25/1ए बेटी रोड नया कट्टरा

प्रयागराज से मुद्रित।

UPHIN 2001/9025

नई दिल्ली। दिल्ली के आजादपुर स्थित लाल बाग इलाके में एक घर में रखिवार को रखाये गए सिलेंडर फटने से 17 लोग घायल हो गए। विस्कोट के कारण पांच घर

भी शक्तिशाली हो गए।

हालांकि, अब तक किसी

की मौत नहीं है। आग की

सुबह करें ताजा रात की अवधि

में अलावा दो लोगों की मौत हो गई।

दोनों लोगों की मौत नहीं है।

दोनों लोगों की मौत नहीं है।